NYCS

युवा सहकार

www.nycsindia.com

दिसंबर 2024, नई दिल्ली

दुनिया ने सुनी भारतीय सहकारिता की धमक

2025

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025

अंदर के पन्नों पर:

- रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहे पैक्स
- बीमा सखी से महिलाएं होंगी आत्मनिर्भर

KRIBHCO
Cooperative and beyond...

Azadi Ka Amrit Mahotsav

Did You Know?

2025 is the International Year of Cooperatives!

The UN declared 2025 as a year to celebrate cooperatives around the world. Cooperatives are businesses owned by their members, focusing on both profit and the needs of their communities. They play a big role in sustainable development and achieving the UN's Sustainable Development Goals by 2030.

There will be a year-long celebration to raise awareness about cooperatives and their positive impact.

युवा सहकार

वर्ष : 01, अंक-06, दिसंबर-2024

निदेशक मंडल
एनवाईसीएस

प्रकाश चंद्र साहू
मनीष कुमार
राजेश बाबूलाल पांडे
प्रकृति क्षितिज पंड्या
बालू गोपालकृष्णन
ज्योतिर्मय सिंह महतो
गौरव पांडेय
हिरेन मधुसूदन शाह
राघव गर्ग
आशुतोष सतीश गुप्ता

कार्यालय

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (एनवाईसीएस)
209, द्वितीय तल, ए2बी, वर्द्धमान जनक मार्केट, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058
मोबाइल नंबर : 9205595944
लैंडलाइन नंबर : 011-45096652/40153681
E-mail: nycs.ltd@gmail.com
Web: www.nycsindia.com

Registration No
DELBIL/2008/25219

संकल्पना, कंटेंट व डिजाइन : फार्च्यूना कम्यूनिकेशन प्रा. लि., नई दिल्ली

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित एवं पारस ऑफसेट प्रा. लि. कुंडली, हरियाणा द्वारा मुद्रित।

अभिषेक कुमार: पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के उत्तरदायी।

NYCSIndia

सहकारिता से संभव है बेहतर विश्व का निर्माण 04
डॉ. अवस्थी को रोशडेल पायनियर्स अवार्ड 05

06 दुनिया ने सुनी भारतीय सहकारिता की धमक

12 सहकारिता भरेगी नई उड़ान

स्वयं सहायता समूहों से बदल रही महिलाओं की तकदीर 18
फिर दगा दे गई मैन्यूफैक्चरिंग 20
विकास में बढ़े युवाओं की सहभागिता: एनवाईसीएस 23
एनवाईसीएस का स्थापना दिवस 24
सहकारिता से आत्मनिर्भर बनेगा भारत 26
वेजफेड से बिहारी तरकारी को मिले बड़े खरीददार 28
बीमा सखी: दो लाख महिलाओं को मिलेगा रोजगार 30

सहकारिता से संभव है बेहतर विश्व का निर्माण

सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने में संयुक्त राष्ट्र सहकारी समितियों को महत्वपूर्ण मानता है। खासकर दुनियाभर में असमानता कम करने, बेहतर कल्याणकारी उपायों को बढ़ावा देने और गरीबी उन्मूलन में इनकी प्रमुख भूमिका है। वर्ष 2025 विश्व की प्रमुख चुनौतियों का सामना करने में सहकारिता के प्रयासों की वैश्विक पहल होगी।

भारतीय सहकारिता आंदोलन के लिए यह गर्व का विषय है कि वैश्विक सहकारी संस्थाओं के शीर्ष निकाय अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आईसीए) की महासभा और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह पहली बार भारत में आयोजित हुआ। 'सहकारिता सबकी समृद्धि का द्वार' थीम पर आयोजित इस सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की औपचारिक शुरूआत भी हुई। यह पूरी दुनिया में सहकारिता के महत्व को दशार्ता है। नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी भी इस सम्मेलन का प्रमुख सह भागीदार था।

नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुए आईसीए के ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में कोऑपरेटिव के भविष्य का रोडमैप तैयार करने के लिए चार प्रमुख एजेंडा पर सहमति बनी। इनमें पहला है, हमारी सहकारी पहचान की पुनर्पुष्टि करना जिसका अर्थ है अपने मूल्यों और सिद्धांतों के अनुसार जीना, सहकारी शिक्षा में निवेश करना और अपनी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना। दूसरा है, सहायक नीतियों को सक्षम करना यानी हमें ऐसी नीतियों की आवश्यकता है जो सहकारी समितियों को सशक्त बनाएं ताकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में उनकी पूरी क्षमता का उपयोग हो सके। तीसरा मजबूत नेतृत्व का विकास करना है। इसके तहत यह तय किया गया कि हमें समावेशी नेतृत्व विकसित करना चाहिए और महिलाओं, युवाओं एवं अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ने के लिए सशक्त बनाना चाहिए। चौथा एजेंडा स्थायी भविष्य का निर्माण करना है जिसके लिए सहकारी समितियां एआई टेक्नोलॉजी को अपना सकती हैं, फिनटेक के माध्यम से फाइनेंस तक पहुंच बना सकती हैं और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उचित समाधान लागू कर सकती हैं।

भारत में सहकारिता की जड़ें काफी मजबूत हैं। इसे इस बात से समझा जा सकता है कि भारतीय जीवन शैली और संस्कृति का आधार ही एक दूसरे का सहयोग करना। सहकारिता का मूल मंत्र भी यही है। भारत में सहकारिता ने विचार से आंदोलन, आंदोलन से क्रांति और क्रांति से सशक्तिकरण तक का सफर तय किया है। यही वजह है कि वर्तमान में दुनिया की एक चौथाई सहकारी संस्थाएं भारत में हैं जिनके सदस्यों की संख्या करीब 30 करोड़ है। भारत का हर पांचवां व्यक्ति कोऑपरेटिव से जुड़ा हुआ है। इफको, अमूल और कृभको जैसी भारतीय सहकारी संस्थाओं के मॉडल ने दुनिया को सहकार से समृद्धि का रास्ता दिखाया है।

अगले वर्ष को पूरी दुनिया द्वारा अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाए जाने से भारत दुनिया में सहकारिता के अन्य सफल मॉडलों को न केवल अपनाने को प्रेरित होगा, बल्कि अपने अनुभवों से वैश्विक सहकारी आंदोलन को नई दिशा दिखाने में भी सक्षम होगा। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का थीम "सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है" है। सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने में संयुक्त राष्ट्र सहकारी समितियों को महत्वपूर्ण मानता है। खासकर दुनियाभर में असमानता कम करने, बेहतर कल्याणकारी उपायों को बढ़ावा देने और गरीबी उन्मूलन में इनकी प्रमुख भूमिका है। वर्ष 2025 विश्व की प्रमुख चुनौतियों का सामना करने में सहकारिता के प्रयासों की वैश्विक पहल होगी।■

प्रकाश चंद्र साहू
अध्यक्ष, नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड

डॉ. अवस्थी को रोशडेल पायनियर्स अवार्ड

डॉ. वर्गीस कुरियन के बाद यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले दूसरे भारतीय हैं इफको एमडी डॉ. उदय शंकर अवस्थी

युवा सहकार टीम

भारतीय सहकारी आंदोलन को मजबूत करने और सहकारिता क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको) के प्रबंध निदेशक डॉ. उदय शंकर अवस्थी को प्रतिष्ठित रोशडेल पायनियर्स अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है। डॉ. वर्गीस कुरियन के बाद यह पुरस्कार पाने वाले डॉ. अवस्थी दूसरे भारतीय हैं। डॉ. कुरियन को वर्ष 2001 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। रोशडेल पायनियर्स अवार्ड इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस (आईसीए) द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इस अवार्ड की शुरूआत वर्ष 2000 में हुई थी। इसका उद्देश्य सहकारिता के क्षेत्र से जुड़े किसी व्यक्ति या संगठन को मान्यता देना है, जिसने नवीन और वित्तीय रूप से टिकाऊ सहकारी गतिविधियों में योगदान दिया है जिससे उनके सदस्यों को काफी लाभ हुआ है।

केमिकल इंजीनियर डॉ. अवस्थी 1976 में इफको में नियुक्त हुए। उनके नेतृत्व में इस सहकारी संस्था ने अपनी उत्पादन क्षमता में 292 प्रतिशत और शुद्ध संपत्ति में 688 प्रतिशत की वृद्धि की। उनके नेतृत्व में इफको ने विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में कदम रखा है, अपने व्यवसाय में विविधता लाई है और भारत के किसानों के लिए सफलतापूर्वक नवाचार और स्वदेशी नैनो उर्वरक विकसित किया है। आईसीए के अध्यक्ष एरियल ग्वार्को ने भारत में पहली बार आयोजित हुए आईसीए के वैश्विक सहकारी सम्मेलन में डॉ. अवस्थी को यह पुरस्कार प्रदान किया।

डॉ. उदय शंकर अवस्थी ने पुरस्कार ग्रहण करने के बाद कहा, 'मैं इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को पाकर बेहद सम्मानित महसूस कर रहा हूं। यह पुरस्कार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के दृष्टिकोण का प्रतीक है। साथ ही यह गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में इफको के असाधारण प्रयासों को उजागर करता है। हम भारत के सहकारी आंदोलन को वैश्विक मंच पर मजबूती प्रदान करने के उनके दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित हैं। मैं इस सम्मान के लिए अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आईसीए) का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जो हमें विश्व स्तर पर सहकारी भावना को बनाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है।'

डॉ. अवस्थी ने कहा, 'इफको ने नैनो डीएपी और नैनो यूरिया (तरल) जैसे नैनो उर्वरकों के माध्यम से टिकाऊ कृषि का समर्थन किया, कृषि पद्धतियों में बदलाव किया और पर्यावरण-अनुकूल समाधानों की मांग को पूरा किया है। स्वदेशी नैनो उर्वरकों ने लॉजिस्टिक मुद्दों से निपटने, भारत की उर्वरक आयात निर्भरता कम करने और भारी पैकेजिंग को कॉम्पैक्ट बोतलों से बदल दिया। इन नवाचारों ने मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार किया, किसानों की लाभप्रदता को बढ़ावा दिया और पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार खेती को बढ़ावा दिया है। इफको के नए स्वदेशी उत्पाद नैनो यूरिया (तरल) और नैनो डीएपी (तरल) का उपयोग भारत के हर कोने और कुछ अन्य देशों, विशेष रूप से पड़ोसी देशों के किसानों द्वारा व्यापक रूप से किया जा रहा है। भविष्य में हम 25 और देशों में नैनो उर्वरक निर्यात करने की योजना बना रहे हैं।' ■

दुनिया ने सुनी भारतीय सहकारिता की धमक

- सफलतापूर्वक संपन्न हुआ भारत में पहली बार आयोजित आईसीए का वैश्विक सहकारी सम्मेलन
- संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का हुआ औपचारिक आगाज
- सामाजिक समावेशन, आर्थिक सशक्तिकरण और सतत विकास को बढ़ावा देने में सहकारी समितियों की परिवर्तनकारी भूमिका का किया गया आह्वान
- असमानता कम करने, बेहतर कल्याणकारी उपायों को बढ़ावा देने और गरीबी उन्मूलन में इन समितियों की भूमिका है निर्णायक

युवा सहकार टीम

दुनिया के लिए कोऑपरेटिव एक मॉडल है, लेकिन भारत के लिए कोऑपरेटिव संस्कृति का आधार और जीवन शैली है। भारत में सहकारिता ने विचार से आंदोलन, आंदोलन से क्रांति और क्रांति से सशक्तिकरण तक का सफर तय किया है। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन (आईसीए) के वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का 25 नवंबर को उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन शब्दों के साथ जब संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का औपचारिक रूप से आगाज किया तो यह तय हो गया कि भारत सहकारिता के बलबूते न सिर्फ खुद को विकसित देशों की कतार में खड़ा करने के लिए तेजी से कदम बढ़ा चुका है, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था को नई राह दिखाने के लिए

भी तत्पर है। भारतीय सहकारी आंदोलन की मजबूती का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि दुनिया की करीब एक चौथाई सहकारी संस्थाएं (8 लाख) भारत में मौजूद हैं जिनके सदस्यों की संख्या करीब 30 करोड़ है। दुनियाभर में 30 लाख सहकारी संस्थाएं हैं जिनके सदस्यों की संख्या 1.2 अरब है और इस क्षेत्र ने दुनिया के 21 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार दे रखा है। सदस्यों की संख्या के लिहाज से भी भारत का हर पांचवां व्यक्ति सहकारिता से जुड़ा हुआ है।

इफको, अमूल और कृभको जैसी विश्व स्तरीय भारतीय सहकारी संस्थाओं के मॉडल ने दुनिया को सहकार से समृद्धि का जो रास्ता दिखाया है, वह अब रुकने वाला नहीं है और न ही भारत सहकारिता क्षेत्र में अपनी मौजूदा मजबूत स्थिति के बावजूद विराम लेने को तैयार है। 2021 में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद से भारत कोऑपरेटिव मूवमेंट को नया विस्तार दे रहा है। अगले वर्ष को पूरी दुनिया द्वारा अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाए जाने से भारत दुनिया में सहकारिता अन्य सफल मॉडलों को न केवल अपनाने को प्रेरित होगा, बल्कि अपने अनुभवों से वैश्विक सहकारी आंदोलन को नए टूल्स

देने में भी सक्षम होगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का थीम ''सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है'' है। इसमें सामाजिक समावेशन, आर्थिक सशक्तिकरण और सतत विकास को बढ़ावा देने में सहकारी समितियों की परिवर्तनकारी भूमिका का उल्लेख होगा। सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने में संयुक्त राष्ट्र सहकारी समितियों को महत्वपूर्ण

इफको, अमूल और कृभको जैसी विश्व स्तरीय भारतीय सहकारी संस्थाओं के मॉडल ने दुनिया को सहकार से समृद्धि का जो रास्ता दिखाया है, वह अब रुकने वाला नहीं है और न ही भारत सहकारिता क्षेत्र में अपनी मौजूदा मजबूत स्थिति के बावजूद विराम लेने को तैयार है।

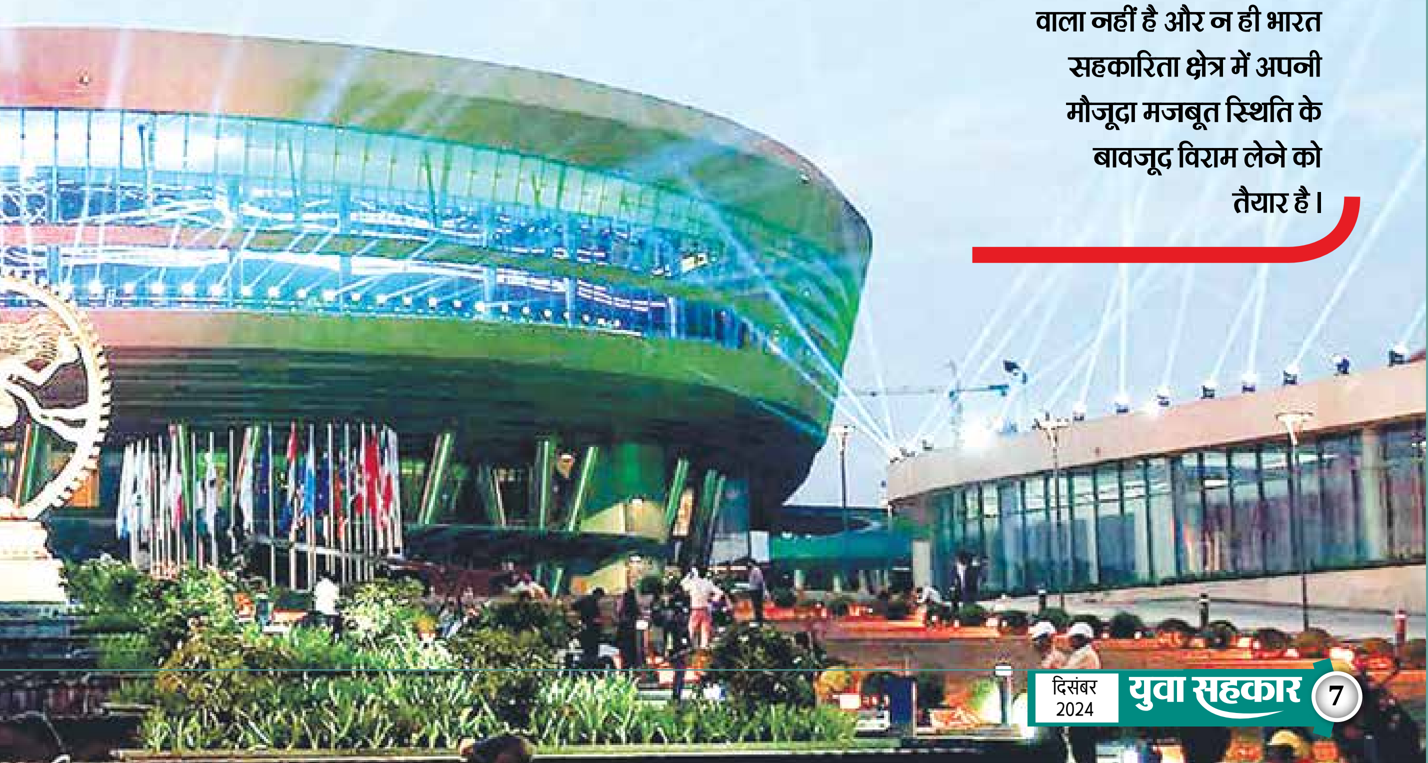

> **सहकारी समितियां चीनी, उर्वरक, मत्स्य पालन और दूध उत्पादन जैसे क्षेत्रों में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। बीते 10 साल में भारत में अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग और हाउसिंग कोऑपरेटिव्स का भी बहुत विस्तार हुआ है। आज भारत में लगभग 2 लाख हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसायटी हैं।**

चालक मानता है। खासकर दुनियाभर में असमानता कम करने, बेहतर कल्याणकारी उपायों को बढ़ावा देने और गरीबी उन्मूलन में इनकी प्रमुख भूमिका है। वर्ष 2025 विश्व की प्रमुख चुनौतियों का सामना करने में सहकारिता के प्रयासों की वैश्विक पहल होगी।

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के दौरान पूरी दुनिया की सहकारी समितियों को एक दूसरे को जानने, समझने और पहचानने का मौका मिलेगा। साथ ही, अपना अनुभव बताने और दूसरों के अनुभव से सीखने का भारतीय सहकारी संस्थाओं को मौका मिलेगा। इसके अलावा, यह कोऑपरेटिव टू कोऑपरेटिव बिजनेस करने और बढ़ाने का अवसर भी देगा। इसके लिए जगह-जगह मीटिंग आयोजित की जाएंगी और सहकारिता की चुनौतियों से निपटने के रास्ते तलाश कर बेहतर विश्व के निर्माण के द्वार खोले जाएंगे।

वैश्विक सहकारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'सहकारिता आंदोलन मुनाफा नहीं मानवता के भाव को आगे लेकर बढ़ता है। दुनिया के लिए यह जरूरी है कि वह विकास को मानव केंद्रित नजरिये से देखे। सहकारिता से वैश्विक सहयोग को नई ऊर्जा मिल सकती है। खासतौर पर ग्लोबल साउथ के देशों को जिस प्रकार की ग्रोथ की जरूरत है उसमें कोऑपरेटिव्स मदद कर सकती हैं। सहकारिता को दुनिया में अखंडता और आपसी सम्मान का ध्वजवाहक बनाने की जरूरत है।' देश के भविष्य के विकास में सरकार सहकारिता की बड़ी भूमिका देखती है। सहकारी समितियों को बहुउद्देशीय बनाने के लक्ष्य के साथ भारत सरकार ने अलग से सहकारिता मंत्रालय बनाकर सहकारिता के पूरे इकोसिस्टम को बदलने का काम किया है। सहकारी क्षेत्र में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने पर भी विचार किया जा रहा है।

सहकारी समितियां चीनी, उर्वरक, मत्स्य पालन और दूध उत्पादन जैसे क्षेत्रों में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। बीते 10 साल में भारत में अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग और हाउसिंग कोऑपरेटिव्स का भी बहुत विस्तार हुआ है। आज भारत में लगभग 2 लाख हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसायटी हैं। इस दौरान सरकार ने कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर में सुधार लाकर उसे मजबूत बनाने का काम किया है। सहकारी बैंकों में 12 लाख करोड़

प्रधानमंत्री के 'सहकार से समृद्धि' के दृष्टिकोण का लक्ष्य सहकारी संस्थाओं को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाना है। आज सहकारिता के अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए नए तरीके खोजने की आवश्यकता है जिसमें वैश्विक सहकारिता सम्मेलन बहुत मददगार साबित हुई है।

रुपये से अधिक जमा हैं, जो इन संस्थाओं के प्रति बढ़ते भरोसे को दशार्ता है। इन बैंकों में डिपॉजिट पर कवर के इंश्योरेंस का बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति डिपॉजिटर कर दिया गया है। कोऑपरेटिव बैंक भी अब डिजिटल बैंकिंग से लैस हैं। इन प्रयासों से भारतीय सहकारी बैंक पहले से कहीं ज्यादा पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी हुए हैं। प्रधानमंत्री के 'सहकार से समृद्धि' के दृष्टिकोण का लक्ष्य सहकारी संस्थाओं को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाना है। आज सहकारिता के अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए नए तरीके खोजने की आवश्यकता है जिसमें वैश्विक सहकारिता सम्मेलन बहुत मददगार साबित हुई है।

21वीं सदी की ग्लोबल ग्रोथ में महिलाओं की भागीदारी काफी मायने रखती है। भारतीय सहकारिता आंदोलन में भी महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है, खासकर दूध उत्पादन और मत्स्य पालन क्षेत्र में। इसलिए भारत का फोकस महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर है, जो दुनिया के लिए महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा मॉडल बन सकता है। आज भारत के सहकारिता क्षेत्र में 60 फीसदी से ज्यादा भागीदारी महिलाओं की है। सहकारी

संस्थाओं के प्रबंधन में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़े, इसके लिए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसायटी एक्ट में संशोधन किया गया है। अब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव

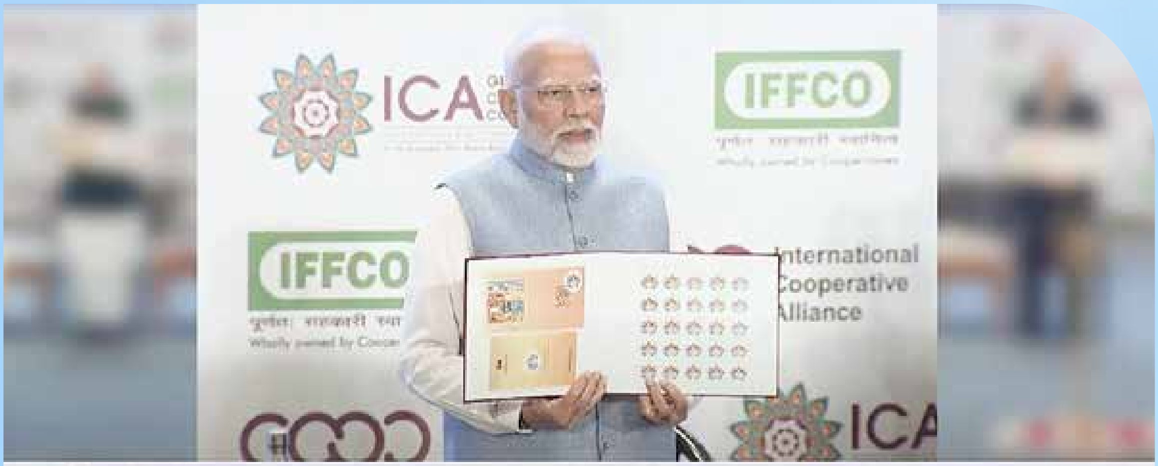

वैश्विक सहकारी सम्मेलन के मंच से 21वीं सदी में वैश्विक सहकारी आंदोलन की दिशा तय करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए सहकारी समितियों के लिए सरल एवं पारदर्शी वित्तपोषण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक सहयोगात्मक वित्तीय मॉडल बनाने का आह्वान किया गया।

सोसायटी के बोर्ड में महिला डायरेक्टर का होना अनिवार्य कर दिया गया है। इतना ही नहीं, इनमें वंचित वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। सहकारी संस्थाओं के अलावा महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से भी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसकी बदौलत देश की 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। इन समूहों को सरकार ने विविध गतिविधियां संचालित करने और उनके सदस्यों के स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 9 लाख करोड़ रुपये का सस्ता लोन दिया है जिसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़ी धन संपत्ति का इजाफा करने में मदद पहुंचाई है। इसके माध्यम से वंचित तबके की महिलाएं अपने परिवार की गरीबी दूर करने के साथ-साथ स्वरोजगार के लिए भी प्रेरित हुई हैं।

वैश्विक सहकारी सम्मेलन के मंच से 21वीं सदी में वैश्विक सहकारी आंदोलन की दिशा तय करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए सहकारी समितियों के लिए सरल एवं पारदर्शी वित्तपोषण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक सहयोगात्मक वित्तीय मॉडल बनाने का आह्वान किया गया। इस तरह के साझा वित्तीय मंच बड़ी परियोजनाओं के वित्तपोषण और सहकारी समितियों को ऋण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया भर में सहकारी समितियों को वित्तपोषित करने में सक्षम वैश्विक वित्तीय संस्थानों के निर्माण की आवश्यकता में आईसीए की बड़ी भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि भविष्य में इससे आगे बढ़ना जरूरी है। दुनिया की मौजूदा स्थिति सहकारी आंदोलन के लिए एक बड़ा अवसर प्रस्तुत करती है।

सहकारिता आंदोलन के प्रति भारत की वचनबद्धता के प्रतीक के रूप में वैश्विक सहकारी सम्मेलन में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग टोबगे, फिजी के उप प्रधानमंत्री मनोआ

टोबगे ने लूट ली महफिल

भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग टोबगे ने वैश्विक सहकारी सम्मेलन के उद्घाटन मौके पर अपने संबोधन की शुरूआत हिंदी में करके महफिल लूट ली। उन्होंने जैसे ही हिंदी में बोलना शुरू किया भारत मंडपम स्थित सम्मेलन हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। टोबगे ने हिंदी में कहा, 'मैं भारत आकर बेहद खुश हूं। मैं खुश हूं क्योंकि जब भी मैं भारत आता हूं मुझे अपने बड़े भाई आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने का मौका मिलता है।' उन्होंने नरेंद्र मोदी की ओर मुखातिब होकर कहा, 'मेरे बड़े भाई आज मैं बहुत खुश हूं।' उनके इस संबोधन पर प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह भी उनकी इस अदा पर काफी देर तक ताली बजाते रहे।

भूटान के प्रधानमंत्री यहीं नहीं रूके। उन्होंने अमित शाह को धन्यवाद देते हुए कहा, 'आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, आपका तहेदिल से धन्यवाद। आपके निमंत्रण की वजह से ही मुझे अपने बड़े भाई से मिलने का अवसर मिला। आपक बहुत शुक्रिया।'

इससे पहले संयुक्त राष्ट्र के भारत में कोऑर्डिनेटर शोम्बी शार्प ने भी अपने संबोधन में हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल कर सम्मेलन में आए लोगों की तालियां बटोरी। उन्होंने हिंदी में कहा, 'आप सभी को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।' उनके यह कहते ही अमित शाह तालियां बजाने लगे और नरेंद्र मोदी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। फिजी के उप प्रधानमंत्री मनोआ कामिकामिका ने भी अपने संबोधन में 'वसुधैव कुटम्बकम' का जिक्र कर सहकार की भावना को प्रबल किया।

कामिकामिका, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, भारत में संयुक्त राष्ट्र के स्थानीय समन्वयक शोम्बी शार्प, आईसीए के अध्यक्ष श्री एरियल ग्वार्को सहित भारत और विभिन्न देशों की सहकारी संस्थाओं के 3000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए।

आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन और आईसीए महासभा का आयोजन आईसीए के 130 साल के इतिहास में भारत में पहली बार आयोजित किया गया जो 25-30 नवंबर तक चला। आईसीए वैश्विक सहकारी आंदोलन का अग्रणी निकाय है। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफको) द्वारा आईसीए और भारत सरकार तथा भारतीय सहकारी संस्थाओं अमूल व कृभको के सहयोग से इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (एनवाईसीएस) की भी इसमें सहभागिता रही। सम्मेलन का विषय 'सहकारिता सबकी समृद्धि का द्वार' था जो भारत सरकार के 'सहकार से समृद्धि' के दृष्टिकोण से मेल खाता है।

इस सम्मेलन में दुनियाभर से आए प्रतिनिधियों ने सहकारिता को आगे बढ़ाने के लिए चर्चाएं की, पैनल डिस्कशन हुआ और कार्यशालाएं आयोजित की गईं। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने में दुनिया भर में सहकारी समितियों के सामने आने वाली चुनौतियों एवं अवसरों, विशेष रूप से गरीबी उन्मूलन, लैंगिक समानता और सतत आर्थिक विकास जैसे क्षेत्रों पर इस दौरान व्यापक विचार-विमर्श किया गया।

महात्मा गांधी कहते थे कि कोऑपरेटिव्स की सफलता उनकी संख्या से नहीं, उनके सदस्यों के नैतिक विकास से होती है। जब नैतिकता होगी तो मानवता के हित में ही सही फैसले होंगे। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष में इसी भाव को सशक्त बनाने के लिए निरंतर काम होगा। ■

सहकारिता से वैश्विक सहयोग को नई ऊर्जा मिल सकती है। खासतौर पर ग्लोबल साउथ के देशों को जिस प्रकार की ग्रोथ की जरूरत है उसमें कोऑपरेटिव्स मदद कर सकती हैं। सहकारिता को दुनिया में अखंडता और आपसी सम्मान का ध्वजवाहक बनाने की जरूरत है।

सहकारिता भरेगी नई उड़ान

संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाने का फैसला दुनिया भर के करोड़ों गरीबों व किसानों के लिए आशीर्वाद साबित होगा

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष में नई सहकारी नीति लाकर केंद्र सरकार भारत के सहकारी आंदोलन को नई दिशा देने का काम करेगी

केंद्र सरकार ने 'सहकार से समृद्धि' के संकल्प के माध्यम से लाखों गांवों, करोड़ों महिलाओं और किसानों की समृद्धि का रास्ता खोला

युवा सहकार टीम

समाज के निचले पायदान पर रहने वाले लोगों को अगर समृद्ध बनाना है तो सहकारिता इसका सबसे कारगर उपाय है। सहकारिता आंदोलन बिना पूंजी वाले लोगों को समृद्ध बनाने का एक बहुत बड़ा साधन बन सकता है। भारत इन लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आईसीए) के वैश्विक सहकारी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की औपचारिक शुरूआत होने से भारत के इन प्रयासों को और मजबूती मिलेगी। इससे भारतीय सहकारिता आंदोलन नई उड़ान भरने में सक्षम होगी।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के शुभारंभ मौके पर कहा, 'संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाने का फैसला दुनिया भर के करोड़ों गरीबों और किसानों के लिए आशीर्वाद साबित होगा। तीन साल पहले ही प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'सहकार से समृद्धि' के संकल्प के माध्यम से देश के लाखों गांवों, करोड़ों महिलाओं और किसानों की समृद्धि का रास्ता खोला है। तीन साल में भारत के सहकारिता क्षेत्र में कई नई गतिविधियां हुई हैं और भारतीय सहकारिता आंदोलन का पुनर्जन्म हुआ है। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष में नई सहकारी नीति लाकर सरकार भारत के सहकारी आंदोलन को नई दिशा देने का काम करेगी।'

वर्ष 2021 में केंद्र में नया सहकारिता मंत्रालय बनाकर सरकार ने पहला बड़ा कदम उठाया। इस दौरान सरकार ने देश में सहकारिता को मजबूत बनाने के लिए जितने कदम उठाये हैं उनकी गूंज अब पूरी दुनिया में सुनाई देने लगी है। सरकार का मानना है कि समाज के पिछड़े, अति पिछड़े, गरीब और

विकास की दौड़ में पीछे छूट चुके लोगों के उत्थान के लिए सहकारिता सबसे सशक्त माध्यम है। इसके लिए सहकारिता आंदोलन को मजबूत करना आवश्यक है। इसी दिशा में सरकार ने 2 लाख नई प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) बनाने का लक्ष्य रखा है। अगले तीन साल में देश का एक भी गांव ऐसा नहीं रहेगा जहां कोई सहकारी संस्था न हो। सरकार ने पैक्स के कार्यक्षेत्र में विस्तार के साथ साथ उन्हें आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने का काम शुरू किया है। इनके लिए नए बायलॉज अपनाने से अब पैक्स डेयरी, मत्स्य पालन, अन्न भंडारण, जन औषधि केंद्र आदि जैसे 30 से अधिक विविध क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने में सक्षम हुए हैं। तीन नई राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्यीय सहकारी समितियों के गठन से सहकारिता का क्षितिज और व्यापक हुआ है। राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड ने विदेशी बाजारों तक किसानों की पहुंच को सुगम बनाया तो राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड ने जैविक प्रमाणीकरण और बाजार पहुंच का मंच तैयार किया। भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड ने उन्नत बीजों की सुलभता सुनिश्चित की है। ये तीनों कोऑपरेटिव्स दुनिया के सहकारिता क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का मार्गदर्शन करेंगी। आने वाले दिनों में किसानों की सहभागिता दुनिया के व्यापार में तो बढ़ाएंगी ही, साथ ही पूरी दुनिया की सहकारी संस्थाओं को प्रेरणा देने का काम भी करेगी कि किस प्रकार से छोटा किसान भी पूरी दुनिया के बाजारों तक पहुंच सकता है।

वित्तीय सहायता, कर राहत और एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम ने सहकारी चीनी मिलों में नई जान फूंकने का काम किया है। सहकारी बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करने के लिए सहकारी संस्थाओं के पैसे को सहकारी बैंकों में ही जमा करने पर जोर है। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के माध्यम से सहकारी समितियों को पारदर्शी बनाने और प्रचालन प्रक्रिया को आसान बनाने से देश के सहकारी रूप से कम विकसित क्षेत्रों में सहकारी समितियों की पहुंच बनी है। इसके अतिरिक्त सरकार एक समग्र और व्यापक नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति पर भी काम कर रही है। कमजोर पड़ रही सहकारी संस्थाओं में जान फूंकने से लेकर उनके व्यापार को सरल बनाना, समितियों में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए मजबूत प्रशासनिक, नीतिगत और कानूनी उपाय किए गए हैं। सहकारी संस्थाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए सहकारी नेटवर्क का विस्तार कर एक नया आर्थिक मॉडल खड़ा किया जा रहा है जो भारत की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने में सहायक साबित होगा।

नए सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद सहकारिता क्षेत्र के पूरे कानूनी ढांचे का सुदृढ़ीकरण हुआ है, श्वेत क्रांति 2.0 और नीली क्रांति की शुरूआत भी हुई है जिसमें सहकारिता की भूमिका बहुत अहम है। आने वाले दिनों में सहकारिता विश्वविद्यालय की भी शुरूआत होने जा रही जिसके माध्यम से प्रशिक्षित और तकनीक से युक्त मानव संसाधन का निर्माण होगा। सहकारिता की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार हर गांव और किसान को सहकारिता से जोड़ने के प्रति कटिबद्ध है। गावों, किसानों, महिलाओं और गरीबों के सशक्तिकरण के लिए सहकारिता आंदोलन ने कई रास्ते खोले हैं। इसके माध्यम से आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री के 'सहकार से समृद्धि' के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

भारत में प्राचीन काल से ही सहकारिता का एक समृद्ध इतिहास रहा है। इसके संकेत कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मिलते हैं जहां गांवों में सार्वजनिक लाभ के लिए मंदिरों और बांधों के निर्माण में सामूहिक प्रयासों का उल्लेख है। दक्षिण भारत में भी निधियों का प्रचलन सहकारी वित्तीय व्यवस्था की झलक प्रदान करता है। भारत जैसे विशाल देश में 130 करोड़ से अधिक नागरिकों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए सहकारिता ही सर्वश्रेष्ठ मॉडल है। ■

समाज के पिछड़े, अति पिछड़े, गरीब और विकास की दौड़ में पीछे छूट चुके लोगों के उत्थान के लिए सहकारिता सबसे सशक्त माध्यम है। इसके लिए सहकारिता आंदोलन को मजबूत करना आवश्यक है। इसी दिशा में सरकार ने 2 लाख नई प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) बनाने का लक्ष्य रखा है। अगले तीन साल में देश का एक भी गांव ऐसा नहीं रहेगा जहां कोई सहकारी संस्था न हो।

केंद्र में खाली हैं 10 लाख पद

वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2023 तक 9.7 लाख पद खाली

कुल स्वीकृत पदों का है एक चौथाई, ग्रुप बी (अराजपत्रित) में 33 फीसदी रिक्तियां

ग्रुप सी में 8.27 लाख पदों पर भर्तियों की है गुंजाइश, ग्रुप ए में 22.64 फीसदी पद खाली

युवा सहकार टीम

इस साल अक्टूबर में जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रोजगार मेले के जरिए 51000 नियुक्ति पत्र चयनित युवाओं को सौंपे थे तो इस बात का अंदाज किसी को नहीं था कि अभी केंद्र सरकार के पास देने के लिए इतनी ज्यादा नौकरियां पेंडिंग हैं। लेकिन वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट से यह बात स्पष्ट हो रही है कि सरकार के पास नौकरियों के नौ लाख से भी ज्यादा पद रिक्त पड़े हैं। दिलचस्प बात यह है कि सरकार के पास ये पिछले तीन साल से रिक्त पदों की संख्या बकाया है। सरकारी महकमों के लिए ग्रुप ए से लेकर ग्रुप सी की श्रेणी में विभिन्न पदों पर 40 लाख से अधिक पद स्वीकृत हैं। लेकिन पिछले तीन साल से सरकारी नौकरियों में चार में से एक पद रिक्त है। मार्च 2023 तक ऐसे पदों की संख्या 9.7 लाख थी। यह कुल पदों का करीब 24 परसेंट है।

केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के वेतन व भत्तों से संबंधित नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक, संख्या के लिहाज से सबसे ज्यादा रिक्त पद ग्रुप सी श्रेणी के हैं। इस ग्रुप में 8.27 लाख से ज्यादा पद खाली है। जबकि प्रतिशत के मामले में सबसे ज्यादा ग्रुप बी में अराजपत्रित वर्ग के लिए उपलब्ध कुल स्वीकृत पदों के 33 फीसद से अधिक पद रिक्त हैं। जबकि सबसे कम रिक्त पद ग्रुप बी के राजपत्रित वर्ग में करीब 16 फीसदी हैं। इतनी बड़ी संख्या में पद रिक्त क्यों हैं इसका स्पष्टीकरण रिपोर्ट में नहीं है। लेकिन मोटे तौर पर चयन प्रक्रिया लंबी और अक्सर किन्हीं कारणों से रद्द होने की वजह से नियुक्तियों में होने वाली देरी को इसकी वजह माना जा रहा है। जानकारों का मानना है कि नियुक्तियों का अनुपात हर साल सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों की संख्या से बेहद कम रहता है। इस वजह से भी रिक्त पदों पर नियुक्ति लंबित रह जाती है।

रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2023 तक केंद्र सरकार में ग्रुप ए की श्रेणी में स्वीकृत पदों की संख्या 1.44 लाख से अधिक थी। इनमें से करीब 1.12 लाख पदों भरे जा चुके हैं। 32 हजार से अधिक पद अभी भी रिक्त हैं। इसी तरह ग्रुप बी में राजपत्रित अधिकारियों की श्रेणी में 1.18 लाख से अधिक पद स्वीकृत हैं। परंतु इनमें से 99.5 हजार पदों पर ही भर्ती हुई है। इस तरह 18 हजार से अधिक पद खाली हैं। ग्रुप बी में ही

गैर राजपत्रित कर्मियों की स्वीकृत संख्या 2.96 लाख है, लेकिन नियुक्ति 98.9 हजार पदों पर ही लोग काम कर रहे हैं। ग्रुप सी में स्वीकृत पदों की संख्या 34.8 लाख से अधिक है। इस श्रेणी में भरे जा चुके पदों की संख्या रिपोर्ट के मुताबिक 26.53 लाख से अधिक है।

वैसे सरकार अब रोजगार मेलों के माध्यम से निरंतर इस बात का प्रयास कर रही है कि केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में कर्मचारियों को भरने की रफ्तार को बढ़ाया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 13 रोजगार मेलों के जरिए केंद्र सरकार में रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। अंतिम मेला इसी वर्ष 29 अक्टूबर को हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के लिए 51000 चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे थे। बावजूद केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में लंबित रिक्त पदों की संख्या बनी हुई है। केंद्र के ताजा रोजगार मेले में दिये गये नियुक्ति पत्रों की संख्या ने रिपोर्ट के आंकड़ों का असर चालू वित्त वर्ष की रिपोर्ट में देखने को मिलेगा।

रिपोर्ट के मुताबिक सर्वाधिक लंबित रिक्त पद केंद्र सरकार के पांच विभागों में हैं। रेलवे, रक्षा (सिविल), गृह, डाक और राजस्व विभागों के हिस्से में कुल लंबित रिक्त पदों का लगभग 92 फीसदी है। रेलवे देश में सबसे ज्यादा नौकरियां उपलब्ध कराता है। रिपोर्ट के आंकड़ों के हिसाब से केंद्र सरकार के कर्मचारियों में 10 में से चार कर्मचारी रेलवे के हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो रेलवे केंद्र की 10 नौकरियों में से चार नौकरियों के अवसर प्रदान करता है। रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे में मार्च 2023 तक कुल स्वीकृत पदों की संख्या 14.89 लाख थी। लेकिन इनमें से फिलहाल 11.73 लाख पदों पर ही लोग काम कर रहे हैं। रेलवे के पास अभी भी तीन लाख से भी अधिक रिक्त पद हैं जिन पर नियुक्ति लंबित है।

इसके बाद नंबर आता है रक्षा विभाग में सिविल पदों पर नियुक्त होने वाले कर्मचारियों का। इस वर्ग में विभाग के लिए स्वीकृत पदों की संख्या है 5.77 लाख है। इनमें से केवल 3.33 लाख पदों पर ही लोग काम कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2.44 लाख पद अभी रिक्त हैं और नियुक्ति की बाट जोह रहे हैं। डाक विभाग के लिए 2.50 लाख से कुछ अधिक पद स्वीकृत हैं, लेकिन 1.77 लाख से कुछ ज्यादा पदों पर ही नियुक्तियां हुई हैं। शेष अभी भी खाली हैं। इनमें केंद्रशासित प्रदेशों का आंकड़ा शामिल नहीं है।

रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार का वेतन और भत्तों पर होने वाला व्यय निरंतर बढ़ रहा है। इनमें बोनस, आवास भत्ता, अतिरिक्त अर्जित अवकाश के एवज में किया जाने वाला भुगतान और अवकाश यात्रा भत्ता यानी एलटीसी शामिल है। वित्त वर्ष 2022-23 में पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले वेतन और भत्तों पर होने वाले व्यय में सात फीसद की वृद्धि दर्ज की गई। इस मद में केंद्र सरकार ने 2.75 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया जो इसके पिछले वर्ष 2.56 लाख करोड़ रुपये था। इस व्यय में 80 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी रेलवे, रक्षा, गृह, डाक और राजस्व विभागों की ही थी।

युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। जानकारों का कहना है कि अकेले सरकारी नौकरियों से बेरोजगारी को दूर नहीं किया जा सकता। निजी क्षेत्र की भूमिका इसमें बहुत अधिक है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के चालू वित्त वर्ष के बजट में एक इंटर्नशिप स्कीम की शुरूआत की गई है। इसमें पांच लाख युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर मिलेगा। सरकार का यह प्रयास देश से बेरोजगारी खत्म करने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। ■

केंद्रीय कर्मचारियों के स्वीकृत और खाली (1 मार्च, 2023 तक) पड़े पद (केंद्र शासित प्रदेश सहित)

ग्रुप	स्वीकृत पद	मौजूदा कर्मचारियों की संख्या	खाली पड़े पद	स्वीकृत पद की तुलना में खाली पद का प्रतिशत
ए	1,44,755	1,11,979	32,776	22.64
बी (राजपत्रित)	1,18,264	99,544	18,720	15.83
बी (अराजपत्रित)	2,96,036	1,97,095	98,941	33.42
सी	34,80,827	26,53,332	8,27,495	23.77
कुल	40,39,882	30,61,950	9,77,932	24.21

स्रोतः केंद्रीय वित्त मंत्रालय

सरकार अब रोजगार मेलों के माध्यम से निरंतर इस बात का प्रयास कर रही है कि केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में कर्मचारियों को भरने की रफ्तार को बढ़ाया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 13 रोजगार मेलों के जरिए केंद्र सरकार में रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। अंतिम मेला इसी वर्ष 29 अक्टूबर को हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के लिए 51000 चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे थे।

नए अवसर पैदा कर रहे पैक्स

सहकारिता क्षेत्र को देश की आर्थिक समृद्धि का आधार बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से दर्जनों पहल की गई है। पिछले महीने ही अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आईसीए) जो विश्व की सहकारी संस्थाओं की शीर्ष निकाय है, की आम सभा और वैश्विक सहकारी सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित की गई जिसमें संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की औपचारिक शुरूआत की गई। इन मुद्दों पर केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल सिंह गूजर से **एसपी सिंह** और **अभिषेक राजा** ने विस्तृत बातचीत की। पेश हैं उनके मुख्य अंशः

कोऑपरेटिव सेक्टर को मजबूती के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो बदलाव किए जा रहे हैं उसमें युवाओं के लिए क्या संभावनाएं हैं?

केंद्र सरकार द्वारा सहकारिता क्षेत्र में किए गए सुधार और पहलों ने युवाओं के लिए रोजगार, उद्यमिता, कौशल विकास और नेतृत्व के कई नए अवसर खोले हैं। इन सुधारों का उद्देश्य सहकारी समितियों को मजबूत, आधुनिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सके। सहकारिता क्षेत्र में विविध व्यावसायिक गतिविधियों को शामिल किया जा रहा है, जैसे पैक्स द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर्स (सीएससी), प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, पेट्रोल और डीजल पंप, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप आदि का संचालन। ये गतिविधियां न केवल युवाओं के लिए प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न कर रही हैं, बल्कि उन्हें स्थानीय स्तर पर आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भी प्रदान कर रही हैं। डिजिटलीकरण के प्रयासों से सहकारी समितियों का कार्यक्षेत्र और अधिक आधुनिक हो गया है। पैक्स कम्प्यूटरीकरण परियोजना के तहत 40,000 से अधिक पैक्स को ईआरपी आधारित सॉफ्टवेयर पर लाया गया है। इससे पैक्स की पारदर्शिता और कार्यक्षमता बढ़ी है जिससे किसानों के बीच विश्वास में वृद्धि हुई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन एवं माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र में किए जा रहे बदलाव युवाओं को तकनीकी उन्नति, नीति निर्माण और निगरानी में भाग लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये प्रयास न केवल ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद कर रहे हैं, बल्कि उन्हें रोजगार के नए और स्थायी साधन प्रदान कर रहे हैं।

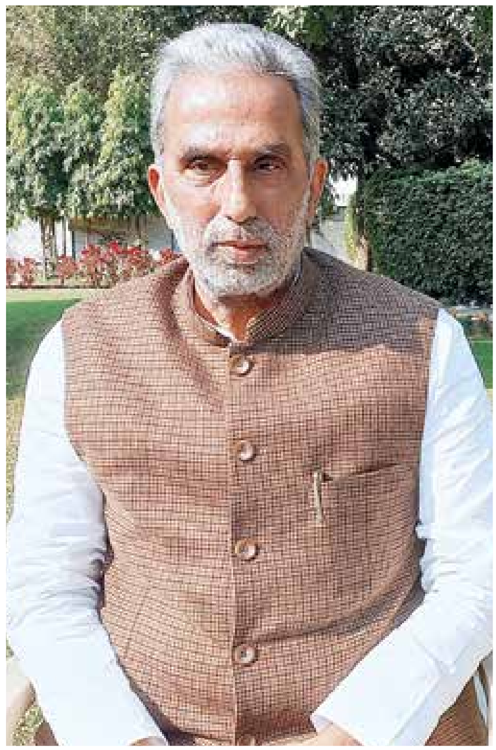

कोऑपरेटिव सेक्टर में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या-क्या किया जा रहा है?

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय और इसके विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और संगठनों जैसे नेशनल काउंसिल ऑफ कोऑपरेटिव ट्रेनिंग (NCCT), वैकुंठ मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट (VAMNICOM), लक्ष्मणराव इनामदार नेशनल एकेडमी फॉर कोऑपरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट (LINAC) आदि के माध्यम से सहकारी सिद्धांतों और उनके लाभों को युवाओं तक पहुंचाने के लिए सहकारी

प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन और अन्य कौशल विकास से संबंधित शिक्षण, प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन संस्थानों के माध्यम से हर वर्ष लगभग 6 लाख प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके साथ ही नई बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य पालन सहकारी समितियों की स्थापना से युवाओं को कृषि, मत्स्य पालन, डेयरी, प्रसंस्करण और कृषि मशीनरी आदि जैसे कार्यकलापों के साथ जुड़ने के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। कौशल विकास के क्षेत्र में भी सहकारिता क्षेत्र ने युवाओं के लिए कई नए अवसर पैदा किए हैं। पैक्स को कॉमन सर्विस सेंटर्स (सीएससी) के रूप में विकसित किया जा रहा है जो युवाओं को डिजिटल सेवाओं और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का उपयोग करने का मौका दे रहा है। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों के उन्नयन से युवाओं को कृषि परामर्श, मृदा और बीज परीक्षण इत्यादि में विशेषज्ञता हासिल करने का अवसर मिल रहा है।

सहकारी क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए जो बदलाव किए गए हैं उनके व्यापक परिणाम जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिले हैं। इसमें कितना समय और लगेगा ताकि सहकार से समृद्धि की परिकल्पना साकार हो सके?

वर्ष 2021 में सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद से सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने और इसे ग्रामीण समृद्धि का आधार बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलें की गई हैं। इन पहलों से ग्रामीणों की सभी जरूरतें गांव और पंचायत स्तर पर ही पूरी हो रही हैं तथा पैक्स की आय में भी वृद्धि हो रही है। परंपरागत रूप से पैक्स पहले केवल ऋण देने तक सीमित थे। वे अब बहुउद्देशीय आर्थिक इकाइयों में परिवर्तित हो रहे हैं। पैक्स के सदस्यों को नई व्यावसायिक गतिविधियों जैसे डिजिटल सेवाएं, आधुनिक रिटेल और कृषि परीक्षण में प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके अलावा, गोदामों और प्रसंस्करण इकाइयों जैसी परियोजनाओं के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण में समय लगता है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए सहकारिता के माध्यम से समृद्धि की दृष्टि को पूरी तरह साकार करना एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। यह एक चुनौतीपूर्ण यात्रा है, लेकिन सहकारिता क्षेत्र में किए गए बदलावों की नींव मजबूत है और प्रगति लगातार हो रही है।

भारत में पहली बार आयोजित हुए इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस (आईसीए) के ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस से भारतीय सहकारी आंदोलन को कितनी मजबूती मिलेगी?

भारत में सहकारिता का इतिहास 100 वर्षों से भी अधिक पुराना है। आईसीए की आम सभा एवं वैश्विक सम्मेलन का आयोजन आईसीए के 130 वर्षों के इतिहास में पहली बार भारत में (25-30 नवंबर 2024) आयोजित हुआ है। यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना को भारत ही नहीं, विश्व स्तर पर पहुंचाने में निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस सम्मेलन में सहकारिता से जुड़े उत्पादों और नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकी के लिए प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें देश के सहकारी विक्रेताओं को दुनिया को अपना हुनर दिखाने का सुनहरा मौका मिला। यह सम्मेलन नए संबंध बनाने, विभिन्न संस्कृतियों में सहकारिता का अनुभव करने और ठोस योजनाओं को साथ ले जाने का माध्यम बना।

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। इससे भारतीय सहकारिता क्षेत्र को क्या दिशा मिलेगी?

सहकारिता ही एक मात्र माध्यम है जिससे समाज के सभी वर्गों का आर्थिक विकास संभव है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित करने का निर्णय वैश्विक स्तर पर सहकारिता के महत्व को दर्शाता है। सहकारिता मंत्रालय वैश्विक स्तर पर सहकारिता के लाभों को उजागर करने, सदस्य देशों के बीच अनुभव साझा करने और सहकारी मॉडल को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इस वर्ष के दौरान जागरूकता बढ़ेगी और सहकारिता क्षेत्र में नई नीतियों और कार्यक्रमों को विकसित करने का अवसर मिलेगा। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के दौरान मंत्रालय सभी हित धारकों के समन्वय से देश-विदेश में सालभर विभिन्न गतिविधियां आयोजित करने के लिए एक कार्य योजना तैयार कर रहा है जिसमें राज्य, जिला एवं ग्रामीण स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, गोष्ठियां और सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। देश की सभी सहकारी समितियों में सहकारिता विषय एवं सहकारिता क्षेत्र के सशक्तिकरण पर परिचर्चा की जाएगी। युवाओं को सहकारिता से जोड़ने के लिए भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सहकारिता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष सहायक होगा। ■

सहकारिता क्षेत्र में किए जा रहे बदलाव युवाओं को तकनीकी उन्नति, नीति निर्माण और निगरानी में भाग लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये प्रयास न केवल ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद कर रहे हैं, बल्कि उन्हें रोजगार के नए और स्थायी साधन प्रदान कर रहे हैं।

फ्लिपकार्ट और पॉलिसी वाच इंडिया फाउंडेशन द्वारा फरीदाबाद में आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन करते केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गूजर एवं अन्य।

स्वयं सहायता समूहों से बदल रही महिलाओं की तकदीर

हरियाणा की 57,000 अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनने की ओर अग्रसर

अगले पांच वर्ष में देश की तीन करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य

दयाराम वशिष्ठ

हरियाणा में पिछले 10 वर्षों में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की तस्वीर काफी बदल गई है। आज ये महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। वे अपनी मेहनत से बड़े मुकाम हासिल कर रही हैं। कुछ महिलाएं घर से ही काम करके आत्मनिर्भर बन रही हैं। कल तक जो महिलाएं घरों से बाहर नहीं निकल पाती थीं, आज वो लाखों कमा रही हैं। हरियाणा राज्य आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी प्रदेश की 57 हजार से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इसे लेकर पिछले महीने फरीदाबाद में फ्लिपकार्ट और पॉलिसी वाच इंडिया फाउंडेशन की ओर से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें महिलाओं को डिजिटल सक्षम बनाने की पहल की गई।

केंद्र सरकार भी स्वयं सहायता समूहों की मदद के लिए आगे आई है। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गूजर ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कहा कि सरकार की तरफ से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए एक नया ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया है जो उनकी कमाई का हिस्सा बनेगा। इस कार्यशाला के माध्यम से संगठन से जुड़ी महिलाओं को सशक्त, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संकल्प है कि जब तक देश की महिलाएं सशक्त, आत्मनिर्भर और स्वावलंबी नहीं होंगी तब तक देश सशक्त और आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। इसलिए उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं।

वर्ष 2014 में देश की केवल एक करोड़ महिलाएं ही स्वयं सहायता समूह से जुड़ी थी। आज इनकी संख्या 10 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। इस दौरान स्वयं सहायता समूह की

जो महिलाएं कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, चूल्हा चौका तक ही सीमित रहती थी आज वे महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर न केवल आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक रूप से भी उन्हें मजबूती मिली हैं। फरीदाबाद में साढे बारह हजार से अधिक महिलाएं समूह से जुड़कर विभिन्न तरह के प्रशिक्षण लेकर अपना कारोबार चला रही हैं।

महिलाओं को बैंकों से 9 लाख करोड़ रुपये का सस्ता लोन दिया गया है जिसने उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया है। पहले इन समूहों को 10 लाख रुपये तक का बिना गारंटी के लोन मिलता था लेकिन अब इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है। इसके पीछे का मकसद महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है। सरकार ने अगले पांच वर्ष 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। सरकार मानती है कि महिलाएं सशक्त होंगी तो परिवार सशक्त होगा और परिवार सशक्त होगा तो समाज और देश भी सशक्त बनेगा। देश की जितनी अधिक महिलाएं सशक्त और लखपति दीदी बनेंगी उतनी ही तेजी से भारत विकसित देश के लक्ष्य की ओर बढ़ेगा।

जो महिलाएं कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, चूल्हा चौका तक ही सीमित रहती थी आज वे महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर न केवल आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक रूप से भी उन्हें मजबूती मिली हैं। फरीदाबाद में साढ़े बारह हजार से अधिक महिलाएं समूह से जुड़कर विभिन्न तरह के प्रशिक्षण लेकर अपना कारोबार चला रही हैं। इनमें गांव नरियाला की गीता देवी, गांव फतेहपुर बिल्लौच की प्रीति, तिगांव की राम सखी, गांव जाजरू की रेनू, जुन्हेड़ा गांव की भावना और तिगांव की पूनम शर्मा की कहानी अपने आप में उदाहरण है। नरियाला की गीता देवी ने बताया कि पहले वह भैंस पालती थी और खेती का काम करती थी। उससे जैसे तैसे गुजारा हो पाता था। कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी। आज वह महिलाओं को ट्रेनिंग देकर अच्छा पैसा कमा रही हैं। इसके लिए उन्हें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सम्मानित भी किया है। गीता देवी के मुताबिक, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उसे मुख्यमंत्री के हाथों सम्मान मिलेगा, लेकिन जब सोनीपत में मुख्यमंत्री से सम्मान मिला तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा।

स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को देश के कोने-कोने में पहुंचाने के लिए उनका ई-कॉमर्स से जुड़ना जरूरी है क्योंकि आज दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और टेक्नोलॉजी का युग है। इस कार्यशाला में महिलाओं को इससे जुड़ी जानकारी दी गई। समूह से जुड़ी महिलाएं जो उत्पाद बनाएंगी उसे दुनिया के बाजार में बेचने में फ्लिपकार्ट मदद करेगा। इस कार्यक्रम में फरीदाबाद के विभिन्न ब्लॉकों से 250 से अधिक स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने शिरकत की। ■

सरकार ने अगले पांच वर्ष 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। सरकार मानती है कि महिलाएं सशक्त होंगी तो परिवार सशक्त होगा और परिवार सशक्त होगा तो समाज और देश भी सशक्त बनेगा। देश की जितनी अधिक महिलाएं सशक्त और लखपति दीदी बनेंगी उतनी ही तेजी से भारत विकसित देश के लक्ष्य की ओर बढ़ेगा।

फिर दगा दे गई मैन्यूफैक्चरिंग

> **जुलाई-सितंबर तिमाही में मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र की वृद्धि दर घटकर 2.2 प्रतिशत पर सिमट गई**
>
> **इसका असर जीडीपी पर पड़ा और भारत की विकास दर गिरकर 5.4 प्रतिशत रह गई**
>
> **अर्थव्यवस्था की धीमी रफ्तार से विकास के दावों पर उठे सवाल, विशेषज्ञ लगा रहे 2024-25 में 6.5 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान**

युवा सहकार टीम

दुनिया में सबसे तेजी से दौड़ती अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है। पूरी दुनिया का ग्रोथ इंजन बनने की तैयारी में जुटे भारत की विकास दर चालू वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में घट कर 5.4 प्रतिशत रह गई है। वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 8.1 प्रतिशत थी। सरकार भी मान रही है कि यह चिंताजनक तो नहीं लेकिन निराशाजनक जरूर है क्योंकि पिछली सात तिमाहियों में यह सबसे कम विकास दर है। इससे पहले अक्टूबर-दिसंबर 2022 की तिमाही में विकास दर इससे कम 4.3 प्रतिशत रही थी। जीडीपी के ताजा आंकड़ों को देखते हुए विशेषज्ञ भी मान रहे हैं कि वित्त वर्ष 2024-25 में विकास दर घटकर 6.5 प्रतिशत के आसपास रह सकती है। यह सुस्ती बड़ा झटका है, खासकर तब जब रोजगार सृजन अभी भी सरकार का एक अधूरा वादा है। कमजोर विकास दर रोजगार बढ़ाने और जीवन स्तर सुधारने के प्रयासों को जटिल बनाता है।

अर्थव्यवस्था की धीमी रफ्तार से सरकार के विकास के दावों पर सवाल खड़े हो गए हैं। यह सरकार के 2030 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य के लिए भी झटका साबित हो सकती है। इस सुस्ती के पीछे कई कारण हैं। लोगों की आमदनी कम हो रही है, कंपनियों का मुनाफा घट रहा है, महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है। इन सबका असर आर्थिक गतिविधियों पर पड़ रहा है। कोरोना महामारी से जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, तब सरकार के कदमों से भारतीय अर्थव्यवस्था जिस तेजी से उबरने में कामयाब रही और जिस रफ्तार से दौड़ लगाई उससे पूरी दुनिया हैरान रह गई। यही वजह थी कि पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिक गई और भारत ने दुनिया का ग्रोथ इंजन बनने की शुरूआती राह पकड़

ली। मगर इस एक झटके ने वास्तविकता को उजागर कर दिया और इसने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। महंगाई आर्थिक विकास की रफ्तार में सबसे बड़ा रोड़ा बनती दिखाई दे रही है। इसलिए सरकार के भीतर और बाहर यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि क्या रिजर्व बैंक को महंगाई को नजरअंदाज कर आर्थिक विकास की दर बढ़ाने के लिए ब्याज दरों में कमी करना चाहिए? जानकारों का मानना है कि इस समय आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दरों में थोड़ी कम लाकर कर्ज की उपलब्धता बढ़ाने की जरूरत है जो अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाएगी।

दूसरी ओर, अभी तक आरबीआई का पूरा फोकस महंगाई को नियंत्रित करने पर है। इसलिए वह पिछले करीब दो साल से ब्याज दरों में कटौती नहीं कर रहा है। इसके बावजूद महंगाई ज्यादातर समय लगातार आरबीआई के निर्धारित दायरे से बाहर ही रही है, खासकर खाद्य महंगाई ने तो आम जनता के जीवन को काफी प्रभावित किया है। इस आंकड़े के आने से पहले ही सरकार में यह सवाल उठने लगा था कि आरबीआई ने 2024-25 के लिए 7.2% की आर्थिक वृद्धि का अनुमान क्यों लगाया, जबकि संकेत अच्छे नहीं थे। सरकार इस बात को लेकर चिंतित है कि आरबीआई का ज्यादा ध्यान खाने-पीने की वस्तुओं और सोने-चांदी की महंगाई पर केंद्रित हो गया है, जबकि इन चीजों की कीमतों पर आरबीआई का ज्यादा नियंत्रण नहीं है। सरकार का कहना है कि आरबीआई के इन चीजों पर ध्यान देने से गैर-खाद्य क्षेत्रों (जैसे निर्माण, उद्योग आदि) की वृद्धि पर असर पड़ रहा है।

धीमी विकास दर और ऊंची महंगाई दर ने आरबीआई के लिए ब्याज दरें घटाने का काम और जटिल बना दिया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि महंगाई को देखते हुए अभी ब्याज दरें कम करना 'बहुत जोखिम भरा' होगा। महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने फरवरी 2023 से ब्याज दरों को न तो घटाया है और न ही बढ़ाया है। इसके बावजूद

खुदरा महंगाई आरबीआई की निर्धारित सीमा 4 प्रतिशत से बार-बार बाहर जा रही है। अक्टूबर में यह 6.2 प्रतिशत थी जो 14 महीने का सबसे ऊंचा स्तर था। इस दौरान खाद्य मुद्रास्फीति 10.87% तक पहुंच गई जो पिछले 15 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर था।

ब्याज दरों में कटौती नहीं होने से क्रेडिट ग्रोथ प्रभावित हो रही है जिससे मैन्यूफैक्चरिंग पर असर पड़ रहा है। मैन्यूफैक्चरिंग का सीधा संबंध रोजगार से है। जब तक मैन्यूफैक्चरिंग में तेजी नहीं आएगी रोजगार के नए अवसर नहीं मिलेंगे और न ही लोगों की आमदनी में ज्यादा वृद्धि होगी। आमदनी नहीं बढ़ने से लोग गैर-जरूरी चीजों पर खर्च करना बंद कर देते हैं जिससे मांग पर असर पड़ता है। मांग प्रभावित होती है तो मैन्यूफैक्चरिंग की वृद्धि दर घट जाती है। भारत के विकास का मुख्य इंजन रहा शहरी मध्यवर्गीय के उपभोग में तेजी से गिरावट आई है। इससे कंपनियों की कमाई घटी है। कंपनियों की रेवेन्यू ग्रोथ 16 तिमाहियों के निचले स्तर पर पहुंच गई है, जो मांग में कमी को दशार्ता है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के आंकड़े भी इसी बात की गवाही देते हैं। इस दौरान विकास दर में गिरावट मुख्य रूप से मैन्यूफैक्चरिंग और खनन क्षेत्र के कारण आई है। मैन्यूफैक्चरिंग में जुलाई-सितंबर तिमाही में सिर्फ 2.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि खनन में 0.1 प्रतिशत की गिरावट आई है। इससे पिछले वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में मैन्यूफैक्चरिंग की वृद्धि दर 14.3 प्रतिशत थी। विकास दर को 5 प्रतिशत

सरकार और आरबीआई के बीच अब यह बहस हो रही है कि क्या महंगाई को नियंत्रित करना ज्यादा जरूरी है या आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना। सरकार का मानना है कि इस समय आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दरों में थोड़ी कम लाकर कर्ज की उपलब्धता बढ़ाने की जरूरत है जो अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाएगी।

ब्याज दरों में कटौती नहीं होने से क्रेडिट ग्रोथ प्रभावित हो रही है जिससे मैन्यूफैक्चरिंग पर असर पड़ रहा है। मैन्यूफैक्चरिंग का सीधा संबंध रोजगार से है। जब तक मैन्यूफैक्चरिंग में तेजी नहीं आएगी रोजगार के नए अवसर नहीं मिलेंगे और न ही लोगों की आमदनी में ज्यादा वृद्धि होगी। आमदनी नहीं बढ़ने से लोग गैर-जरूरी चीजों पर खर्च करना बंद कर देते हैं जिससे मांग पर असर पड़ता है। मांग प्रभावित होती है तो मैन्यूफैक्चरिंग की वृद्धि दर घट जाती है।

से ऊपर ले जाने में कृषि क्षेत्र का बड़ा योगदान रहा है। कृषि क्षेत्र ने अगर बेहतर प्रदर्शन नहीं किया होता तो शायद विकास दर 5 प्रतिशत के नीचे ही रहती। जुलाई-सितंबर 2024 में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 3.5 प्रतिशत दर्ज की गई है जो जुलाई-सितंबर 2023 के 1.7 प्रतिशत की तुलना में दोगुने से ज्यादा है।

मैन्यूफैक्चरिंग सहित पूरे सेकंडरी सेक्टर की चाल सुस्त पड़ने से विशेषज्ञ अब 2024-25 में 6.5% विकास दर का ही अनुमान लगा रहे हैं। हालांकि, सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन का कहना है कि 6.5% विकास दर खतरे का संकेत नहीं है। दूसरी तिमाही में 5.4 प्रतिशत विकास दर को उन्होंने निराशाजनक जरूर करार दिया लेकिन इसे चिंताजनक नहीं माना। नागेश्वरन ने कहा, 'सुस्ती मुख्य रूप से मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर की वजह से है। इसकी एक वजह चीन, जापान और दक्षिण कोरिया से सस्ते स्टील का आयात भी है।' सरकार अभी भी ऊंची विकास दर की बात कर रही है, लेकिन विशेषज्ञ चिंतित हैं। ब्लूमबर्ग के एक सर्वे में 44 अर्थशास्त्रियों में से किसी ने भी इतनी धीमी आर्थिक वृद्धि का अनुमान नहीं लगाया था। रायटर्स के सर्वे में भी अर्थशास्त्रियों ने जुलाई-सितंबर में 6.5% की ग्रोथ का अनुमान लगाया था। हालांकि, अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि बेहतर कृषि उत्पादन, बढ़ते सरकारी खर्च और शादियों के मौसम में खपत में बढ़ोतरी से विकास दर में मामूली सुधार होगा। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की आर्थिक विकास दर वित्त वर्ष 2024-25 में 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

अर्थव्यवस्था की गति धीमी पड़ने का सबसे ज्यादा असर उद्योगों पर पड़ रहा है। पूंजी निवेश की वृद्धि दर दूसरी तिमाही में सिर्फ 5.4 प्रतिशत दर्ज हुई जो पिछले साल की दूसरी तिमाही में 11.6 प्रतिशत थी। इस साल की पहली तिमाही में यह 7.5 प्रतिशत थी। मांग में सुस्ती के कारण उद्योग जगत निवेश करने से हिचकिचा रहा है। नए निवेश के लिए संभव है कि कंपनियां अभी मांग सुधरने और ब्याज दर घटने का इंतजार करें। निर्यात के मोर्चे पर भी स्थिति कमजोर ही है। पहली तिमाही में निर्यात 8.7 प्रतिशत बढ़ने के बाद दूसरी तिमाही में इसकी ग्रोथ घट कर सिर्फ 2.8 प्रतिशत रह गई है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि विकास दर सरकार के पूंजी निवेश पर अधिक निर्भर करेगा।

मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर के लिए हमेशा से घरेलू और निर्यात बाजार उसकी वृद्धि की रफ्तार को तय करते आए हैं। वर्तमान में ये दोनों ही बाजार मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रहे हैं। सस्ते आयात की वजह से कई सेक्टर में घरेलू उत्पादों की मांग प्रभावित हो रही है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने भी यह बात कही है। यही हाल निर्यात बाजार का भी है। सबसे बड़ी दिक्कत उत्पादन की ऊंची लागत की है। चीन समेत कई दक्षिण एशियाई देश लागत के मामले में भारतीय उत्पादों को चुनौती दे रहे हैं। इस बात से किसी को इनकार नहीं होगा कि मैन्यूफैक्चरिंग और व्यापार (घरेलू व विदेश) दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। मैन्यूफैक्चरिंग की गुणवत्ता ही निर्यात को बढ़ाएगी और निर्यात बाजार में पैठ ही मैन्यूफैक्चरिंग को विस्तार का अवसर देगी। बीते एक दशक के अनुभव ने यह साबित किया है कि केवल प्रोत्साहन ही जीडीपी में मैन्यूफैक्चरिंग के योगदान को बढ़ाने के लिए काफी नहीं हैं। उद्योगों के लिए ऐसी टिकाऊ टैक्स और प्रोत्साहन नीति का समन्वय करना होगा जो न केवल लागत कम करे बल्कि आयातित उत्पादों के साथ घरेलू उत्पादों को भी प्रतिस्पर्धी बनाने में मददगार हो। ■

विकास में बढ़े युवाओं की सहभागिता: एनवाईसीएस

युवा सहकार टीम

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी (एनवाईसीएस) इस वर्ष अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर चुका है। इस विशेष अवसर पर संस्था की सफलता और प्रगति की खुशी मनाते हुए संगठन ने पिछले कार्यकाल की उपलब्धियों को साझा किया और भविष्य की दिशा पर विचार विमर्श किया। 25वीं वर्षगांठ मनाते हुए एनवाईसीएस की सभी शाखाओं में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान संगठन के सभी सहकार मित्रों और शेयरधारकों को सराहना के प्रतीक के रूप में दीवार घड़ी दी गई।

इस मौके पर एनवाईसीएस ने शेयरधारकों और सहकार मित्रों के लिए जारी संदेश में कहा, सोसायटी को स्तंभ के रूप में संभाल कर साथ खड़े रहने वाले सहकार मित्र/ शेयरधारक को बहुत-बहुत बधाई। आपके अटूट समर्थन और विश्वास के बिना यह यात्रा संभव नहीं हो पाती। हमने इस दौरान कई महत्वपूर्ण मील के पत्थर को पार किया है। यह सब आपकी निरंतर भागीदारी और सहयोग से संभव हुआ है। युवाओं को सशक्त बनाने और देश को आगे ले जाने में युवाओं की सहभागिता कैसे बढ़े इसका निरंतर प्रयास ही हमारा उद्देश्य है। यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि एम्पावरिंग यूथ, पावरिंग दि नेशन' के इसी उद्देश्य पर हम काम कर रहे है और आगे भी करते रहेंगे। ■

व्यारा में ब्यूटी पार्लर एवं भरतनाट्यम क्लासेस का आयोजन

गुजरात के तापी जिले के व्यारा में एनवाईसीएस की जननिधि शाखा द्वारा महिलाओं एवं लड़कियों के लिए रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत ब्यूटी पार्लर और भरतनाट्यम क्लासेस का आयोजन किया जा रहा है ताकि उनमें आत्मनिर्भरता का स्तर बड़े। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के तहत इन क्लासेस के लिए बहुत ही कम शुल्क लिया जा रहा है। इसका उद्देश्य उन्हें अपने पैरों पर खड़ा कर आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है।

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी (एनवाईसीएस) कौशल विकास के माध्यम से युवाओं की आजीविका के अवसर की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करता है ' एनवाईसीएस अपनी शुरूआत यानी पिछले 25 साल से इसी आधार पर कार्य कर रही है। कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने का प्रयास और बेरोजगार युवाओं को विभिन्न व्यवसायों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना ही एनवाईसीएस का मकसद है। ■

एनवाईसीएस का स्थापना दिवस

युवा सहकार टीम

समर्थ युवा, समर्थ भारत के संस्कारों से प्रेरित नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी (एनवाईसीएस) के देशभर में स्थित शाखाओं में 9 दिसंबर को हर्षोल्लास के साथ स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर अलग-अलग शाखाओं में अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। यह वर्ष एनवाईसीएस की स्थापना का 25वां वर्ष भी है। पिछले 25 साल से यह संगठन देश के युवाओं का मार्गदर्शन करने और ऐसे सभी मौकों से उन्हें अवगत कराने का प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे उनकी जिंदगी में सुधार आ सके। युवाओं के समुचित विकास के लिए उन्हें कुशल व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, खेल प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता उपलब्ध करवा कर उन्हें उद्यमशीलता के मार्ग पर प्रशस्त करना एनवाईसीएस की प्राथमिकता है ताकि युवा वर्ग न केवल अपना, बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र का विकास करने में समर्थ बने।

KOVIDA

NYCS
National Yuva Cooperative Society Limited
Celebrating
26th Foundation Day
8th December, 2024

NYCS
National Yuva Cooperative Society Limited
Celebrating
26th Foundation Day
8th December, 2024

सहकारिता से आत्मनिर्भर बनेगा भारत

सहकार भारती का आठवां राष्ट्रीय अधिवेशन अमृतसर में हुआ संपन्न

सहकारिता को आत्मसात करने वाले राज्य कर रहे हैं तरक्की- राज्यपाल

युवा सहकार टीम

सहकारिता भारतीय जीवन संस्कृति का आधार रही है। देश की ग्रामीण व्यवस्था सहकारिता आधारित थी। यहां के लोग जीवन को सहकारिता के आधार पर जीने के अभ्यस्त थे। मगर बदलते समय के साथ सहकार की भावना में कमी आती चली गई। वर्तमान परिदृश्य में सहकारिता आंदोलन को दोबारा खड़ा करने की जरूरत है। भारत सही मायने में आत्मनिर्भर तभी बन सकेगा जब सहकारिता को लोग अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने सहकार भारती के आठवें राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने पर जोर देते हुए यह बातें कही।

पंजाब के अमृतसर में 6-8 दिसंबर तक आयोजित इस अधिवेशन में 26 सूत्री चार प्रस्ताव पास किए गए। इन प्रस्तावों के आधार पर सहकार भारती की आगे की कार्ययोजना बनाई जाएगी। पहला प्रस्ताव सहकारी क्षेत्र में कानूनों का आधुनिकीकरण तथा सहकारी समितियों को आर्थिक उद्यम के रूप में स्वतंत्रापूर्वक कार्य करने में सक्षम बनाने पर केन्द्रित था। दूसरा प्रस्ताव सहकारी आंदोलन के विकास के लिए प्रशिक्षण, शिक्षा और जागरूकता रहा। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार के प्रति अभिनंदन प्रस्ताव भी पारित हुआ। चौथे प्रस्ताव के रूप में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए सहकारी समितियों को सशक्त बनाने से संबंधित रहा।

अधिवेशन को संबोधित करते हुए गुलाब चंद कटारिया ने कहा, 'अच्छे संस्कारों के बगैर मजबूत सहकार संभव नहीं है। वर्तमान समाज को सहकारिता से जोड़ना जरूरी है। जिन राज्यों ने सहकारिता को आत्मसात किया वह आज तरक्की पर है। सहकारिता में जिन लोगों ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद को बढ़ावा दिया उन्हीं लोगों ने सहकारिता का

बंटाधार किया। ऐसे समय में सहकार भारती ही इसका उद्धार कर सकती है।' गुजरात का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि गुजरात में तरक्की का आधार सहकारिता ही है। पंजाब में सहकारिता की अपार संभावनाएं हैं। यहां इस क्षेत्र में कार्य करने की बहुत जरूरत है। यहां के प्रत्येक शहर और गांव में ऐसे लोगों को जोड़ना होगा जो अपने साथ सहकारिता की चेन बनाकर इसे आगे बढ़ा सकें।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने इस मौके पर कहा, 'भारत में आजादी के समय से ही सहकारिता आंदोलन की भूमिका अहम रही है। वर्तमान में हम सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए कि सहकारिता की सीमा भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व तक होनी चाहिए। आज हम आर्थिक विकास तो कर रहे हैं लेकिन सामाजिक विकास की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। सामाजिक विकास के लिए पूरे देश में परिवर्तन की लहर चलाने की जरूरत है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, संयमता और न्याय की बात कही गई है। यह कहीं न कहीं पिछड़ रहा है। सही मायने में सहकारिता का अर्थ बेहतर कुटुंब, जनमानस और राष्ट्र का निर्माण करना है जिसमें एक-दूसरे के प्रति संवेदनाएं हों। आज एक-दूसरे के प्रति सामाजिक संवेदनाएं समाप्त होती जा रही हैं। इस तरफ ध्यान दिए जाने की जरूरत है।'

अधिवेशन के समापन मौके पर केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। अधिवेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की तरक्की के लिए गांवों के किसान-मजदूरों को समृद्ध करना जरूरी है। देश की उन्नति में 12-14 प्रतिशत हिस्सेदारी खेतीबाड़ी व इससे जुड़े उद्योगों की है। स्वाधीनता आंदोलन की शुरूआत में 90 फीसदी आबादी गांवों में रहती थी, लेकिन अब 30 फीसदी आबादी गांवों से निकल कर बड़े शहरों में चली गई है। बड़े शहरों में लोग झोपड़-पट्टी में रहने को मजबूर हैं। किसानों

व मजदूरों की हालत अच्छी नहीं है। अगर अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है तो हमें गांव, गरीब, किसान, मजदूर, कृषि और जंगल के क्षेत्र को समृद्ध करना होगा। अगर गांवों का उद्धार करना है तो सहकारिता की प्राथमिकता में किसानों को रखना होगा। यह कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। हमारा किसान अब सिर्फ अन्नदाता नहीं रहा। वह अब ऊर्जा दाता और ईंधन दाता है। सहकार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीनानाथ ठाकुर ने कहा कि 2021 में जब सहकारिता मंत्रालय की स्थापना हुई तो देश में सहकारिता के प्रति एक नई चेतना का निर्माण हुआ। इस बात के लिए हम सभी को गौरवान्वित होना चाहिए कि इसके लिए सबसे अधिक योगदान सहकार भारती का रहा है।

सहकारिता क्षेत्र का जाना-माना चेहरा डॉ. उदय जोशी को अधिवेशन में सर्वसम्मति से संगठन का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। वह दीनानाथ ठाकुर की जगह लेंगे। उनका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। डॉ. जोशी इससे पहले संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री थे। राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में अब दीपक चौरसिया को संगठन में जगह दी गई है। चौरसिया करीब 18 साल से सहकार भारती से जुड़े हैं। इसी अधिवेशन में इफको के एमडी डॉ. उदय शंकर अवस्थी को 'फर्टिलाइजर मैन ऑफ इंडिया' के सम्मान से सम्मानित किया गया। ■

आज हम आर्थिक विकास तो कर रहे हैं लेकिन सामाजिक विकास की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। सामाजिक विकास के लिए पूरे देश में परिवर्तन की लहर चलाने की जरूरत है। सही मायने में सहकारिता का अर्थ बेहतर कुटुंब, जनमानस और राष्ट्र का निर्माण करना है जिसमें एक-दूसरे के प्रति संवेदनाएं हों। आज एक-दूसरे के प्रति सामाजिक संवेदनाएं समाप्त होती जा रही हैं। इस तरफ ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

वेजफेड से बिहारी तरकारी को मिले बड़े खरीददार

बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण और विपणन योजना से जुड़े 50 हजार सब्जी किसान

पीवीसीएस के माध्यम से होता है सब्जियों का प्रसंस्करण और विपणन

युवा सहकार टीम

बिहार भारत के शीर्ष पांच सब्जी उत्पादक राज्यों में शामिल है। यहां आलू, प्याज, बैंगन फूल गोभी आदि कई सब्जियों का उत्पादन होता है। गंगा की तलहटी में होने के कारण यहां के कई क्षेत्रों की जमीन सब्जियों की अच्छी पैदावार के लिए मुफीद है। लेकिन सब्जी उत्पादकों के लिए कई अनुकूल परिस्थितियां होने के बाद भी किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल पाता था, और सब्जी उत्पादन किसानों के लिए घाटे का सौदा साबित होता था। किसानों को सब्जियों का उचित मूल्य दिलाने और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बिहार सरकार ने वेजफेड बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण और विपणन योजना शुरू कीयह एक कोऑपरेटिव फर्म है जिसके मालिक खुद किसान ही होते हैं।

वर्ष 2017 में शुरू की गई इस योजना से बिहार सरकार ने सहकारिता के माध्यम से असंगठित सब्जी बाजार को एक संगठित बाजार में बदल दिया है। वेजफेड के तहत सभी किसान मिलकर ब्लॉक स्तर पर प्राइमरी वेजिटेबल कोऑपरेटिव सोसाइटी (पीवीसीएस) बनाते हैं। यह सारे पीवीसीएस मिलकर यूनियन बनाते हैं और सभी यूनियन मिलकर राज्य में वेजफेड या वेजिटेबल फेडरेशन बनाती हैं। इस योजना का उद्देश्य राज्य में उत्पादित सब्जियों का विपणन करके तरकारी ब्रांड को स्थापित करना है। वहीं पीवीसीएस का मुख्य उद्देश्य किसान सदस्यों से सब्जियों का संग्रह और प्राथमिक प्रसंस्करण करके उन्हें अपने संबंधित संघों को आपूर्ति करना है, ताकि किसानों को उनका उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित किया जा सके। हर थाली में बिहारी तरकारी वेजफेड की प्राथमिकता है। इसके साथ ही वेजफेड का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर ताजी सब्जियां उपलब्ध कराना है।

सब्जियों के विपणन के लिए त्रिस्तरीय संरचना

सब्जियों के प्रसंस्करण और उचित मूल्य के लिए एक त्रिस्तरीय स्थाई मॉडल तैयार किया गया। पहले चरण में प्रमुख जगहों पर आउटलेट्स बनाए गए, सब्जियों के विपणन के लिए डोर टू डोर व्यवस्था की गई, मोबाइल रिटेल वैन से सब्जियों को घरों तक पहुंचाया गया, इसके साथ ही डिजिटलीकरण का प्रयोग करते हुए सब्जियों की ऑनलाइन बुकिंग की सेवा भी शुरू की गई। इस तरह एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला बनाई गई। थोक विक्रेता क्योंकि सीधे पीवीसीएस से सब्जियां खरीदते हैं इसलिए उसी दिन बैंक के माध्यम से सब्जियों का भुगतान सीधे किसानों के खाते में कर दिया जाता है। प्रत्येक पीवीसीएस पर सब्जियों की छंटाई, सफाई और ग्रेडिंग की जाती है, ताजी सब्जियों के अस्थाई भंडारण के लिए परिसर में ही दस टन मल्टी कोल्ड स्टोरेज चेंबर सुविधा की जाती है, यहां से सभी सब्जियों को यूनियन को भेजा जाता है, यूनियन से सब्जियों को राज्य और अन्य राज्यों को भेजा जाता है। यह सारा सिस्टम ऑनलाइन संचालित होता है, जिससे संस्थाओं को यह पता होता है कि कितनी सब्जियों का उत्पादन हो रहा है और बाजार में उसकी कितनी मांग है।

सफल आउटलेट्स में भी वेजफेड की तरकारी

वर्तमान में वेजफेड ने कुछ बड़े संस्थान जैसे सफल को भी सब्जियों की आउटसोर्सिंग शुरू की है। वेजफेड की इस योजना से राज्य के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान हो रहे हैं, प्रसंस्करण और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा से किसानों की सब्जियां खराब होने से बच रही हैं। केवल सब्जियों की खरीददारी ही नहीं वेजफेड किसान क्रेडिट कार्ड, खाद, उन्नत बीज, सही दवा आदि का भी प्रशिक्षण देता है। इससे न केवल सब्जी उत्पादन की लागत में कमी आती है बल्कि किसान सब्जियों के उत्पादन के लिए कर्ज लेने के भी मजबूर नहीं होते।

50,000 सब्जी उत्पादक किसान बने सदस्य

वेजफेड द्वारा सब्जियों के लिए तैयार मंच का फायदा सब्जी विक्रेताओं को खूब हो रहा है, खरीदार मिलने की वजह से बिहार मे अब सब्जी किसान बढ़चढ़ कर इस योजना में शामिल हो रहे हैं। बिहार में अब तक 20 जिलों में 321 सब्जी सहकारी समितियों का गठन किया जा चुका है। इन 321 सब्जी उत्पादक समितियों में लगभग 50,000 सब्जी उत्पादक सदस्य किसान इन समितियों के सदस्य हैं। वेजफेड का उद्देश्य राज्य में सब्जी उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, उत्पाद के प्रसंस्करण, पैकेजिंग और ब्रांडिंग द्वारा मूल्य संवर्धन करना, मांग के अनुसार ताजी गुणवत्तापरक सब्जियों की आपूर्ति करना, रोजगार के अवसर पैदा कर सब्जी उत्पादकों की आय में वृद्धि करना, व्यवस्था से बिचौलियों को खत्म करना, व्यवसाय की खुदरा बिक्री के लिए रिटेल दुकानों की स्थापना, संघ स्तर पर केंद्रीय सब्जी प्रसंस्करण केंद्र का निर्माण करना और पीवीसीएस स्तर पर केंद्रों और विपणन के बुनियादी ढांचे को स्थापित करना है। हर थाली में बिहारी तरकारी टैग लाइन के साथ वेजफेड इन सब्जियों को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। ■

वेजफेड के तहत सभी किसान मिलकर ब्लॉक स्तर पर प्राइमरी वेजिटेबल कोऑपरेटिव सोसाइटी (पीवीसीएस) बनाते हैं। यह सारे पीवीसीएस मिलकर यूनियन बनाते हैं और सभी यूनियन मिलकर राज्य में वेजफेड या वेजिटेबल फेडरेशन बनाती हैं। इस योजना का उद्देश्य राज्य में उत्पादित सब्जियों का विपणन करके तरकारी ब्रांड को स्थापित करना है।

बीमा सखी

दो लाख महिलाओं को मिलेगा रोजगार

युवा सहकार टीम

महिलाओं, खासकर ग्रामीण और वंचित तबके की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना केंद्र सरकार की प्राथमिकता में है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लखपति दीदी, ड्रोन दीदी जैसी योजनाओं के बाद अब बीमा सखी योजना की शुरुआत की गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना का मकसद सबके लिए जीवन बीमा के लक्ष्य को हासिल करने के साथ साथ ग्रामीण भारत में बीमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत में इस योजना को लॉन्च किया।

यह योजना खासतौर पर ग्रामीण महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है ताकि उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। इससे न केवल वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगी, बल्कि उन्हें एक स्थिर और सम्मानजनक करियर का रास्ता भी मिलेगा। प्रधानमंत्री का यह प्रयास ग्रामीण महिलाओं के जीवन में एक नई दिशा देने की कोशिश है ताकि वे आर्थिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर मजबूत बन सकें। इस योजना के तहत महिलाओं को भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआइसी) के साथ बीमा एजेंट के रूप में काम करने का मौका मिलेगा। इसके माध्यम से देशभर में 3 साल में 2 लाख बीमा सखी तैयार की जाएंगी। योजना की शुरुआत में 35,000 महिलाओं को बीमा एजेंट के रूप में जोड़ा जाएगा। दूसरे चरण 50,000 और महिलाओं को जोड़ा जाएगा। इसी तरह, चरणबद्ध तरीके से कुल 2 लाख महिलाओं को बीमा एजेंट बनाया जाएगा। यह योजना शुरुआत में हरियाणा में लागू होगी और धीरे-धीरे पूरे देश में इसे शुरु किया जाएगा। इन महिलाओं को 3 साल की ट्रेनिंग करनी होगी। ये ट्रेनिंग सरकार की ओर से करवाई जाएगी। ट्रेनिंग के बाद एक परीक्षा पास कर महिलाएं विकास अधिकारी भी बन सकती हैं।

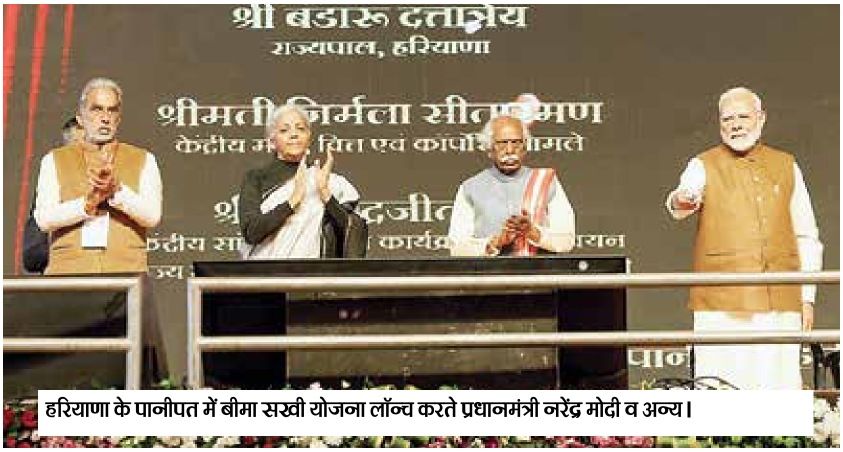

हरियाणा के पानीपत में बीमा सखी योजना लॉन्च करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अन्य।

ट्रेनिंग के दौरान उन्हें स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। पहले साल 7,000 रुपये, दूसरे साल 6,000 रुपये और तीसरे साल 5,000 रुपये मासिक स्टाइपेंड मिलेगा। मगर इसके लिए शर्त है कि पहले साल उनके द्वारा की गई पॉलिसियों में से कम से कम 65% पॉलिसियां दूसरे साल के हर महीने के अंत तक एक्टिव बनी रहें। इसी तरह, दूसरे साल की गई पॉलिसियों में से कम से कम 65% पॉलिसियां तीसरे साल के हर महीने के अंत तक एक्टिव रहें। यानी हर साल का स्टाइपेंड पाने के लिए महिलाओं को अपनी पॉलिसियों को एक्टिव बनाए रखना अनिवार्य होगा। इन शर्तों के हिसाब से काम करने पर पहले साल 84 हजार रुपये, दूसरे साल 72 हजार रुपये और तीसरे साल 60 हजार रुपये स्टाइपेंड के रूप में मिलेंगे। इसके अलावा, इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने पर अलग से कमीशन और टार्गेट पूरा करने पर 2100 रुपये बोनस भी मिलेगा।

कौन होगा पात्र

10वीं कक्षा पास 18-70 वर्ष की महिलाएं इस योजना के तहत बीमा एजेंट बनने के लिए आवेदन कर सकती हैं। हालांकि, एलआइसी एजेंटों या कर्मचारियों के रिश्तेदार, जैसे पति-पत्नी, बच्चे, माता-पिता, भाई-बहन इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते। इसके अलावा, एलआइसी के पूर्व कर्मचारी या पूर्व एजेंट जो दोबारा नियुक्ति चाहते हैं, वे भी इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

जरूरी दस्तावेज

आवेदन प्रक्रिया के दौरान महिलाओं को कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। इनमें हाल की पासपोर्ट साइज फोटो, आयु प्रमाण-पत्र, पता प्रमाण-पत्र और 10वीं की मार्कशीट शामिल हैं। इच्छुक महिलाएं एलआइसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं या फिर अपने नजदीकी एलआइसी ब्रांच से संपर्क कर सकती हैं। ■

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
NCDC
Assisting Cooperatives, Always!

LIFIC

LINAC-NCDC FISHERIES BUSINESS INCUBATION CENTER (LIFIC)

For Cooperatives as Fisheries Bussiness

Set up by NCDC at LINAC
under Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY)
Department of Fisheries,
Ministry of Fisheries, AH & D, Govt of India

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
National Cooperative Development Corporation
Ministry of Cooperation, Govt of India

NANO TECHNOLOGY
NANO UREA & DAP
IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives
IFFCO KISAN DRONE
असरदार जोड़ी
नैनो यूरिया प्लस
सागरिका
नैनो डी ए पी
IFFCO
NANO UREA PLUS
IFFCO
सागरिका
SAGARIKA
100% प्राकृतिक समुद्री उत्पाद
IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives
NANO DAP
(8:16:0)
CROP NUTRITION REDEFINED
Less Cost, More Profits
IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives
इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड
इफको सदन, सी-1, डिस्ट्रिक सेंटर, साकेत प्लेस, नई दिल्ली-110017, भारत
फोन नंबर- 91-11-26510001, 91-11-42592626, वेबसाइट www.iffco.coop
इफको नैनो उर्वरकों के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया स्कैन करें"